कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में आरक्षण कार्यालय

*42 **श्री महेश्वर सिंह**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वह सच है कि दिनांक 14 अगस्त, 1997 को राज्य सभा में 1997-98 की अनुपूरक अनुदान मांगों (रेलवे) पर बहस के दौरान कुल्लू में एक कंप्यूटरीकृत आरक्षण एवं बुकिंग कार्यालय खोलने का मामला उठाया गया था और उन्होने यह आश्वसन दिया था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुल्लू और मनाली विश्व स्तर के पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां पर इस प्रकार का एक कार्यालय खोला जाएगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) कुल्लू में कंप्यूटरीकृत आरक्षण/बुकिंग कार्यालय कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(घ) इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी हां। अन्य बातों के साथ, यह भी कहा गया था कि वहां इन सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) से (घ) व्यावहारिकता रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और राज्य सरकार द्वारा भूमि/इमारत उपलब्ध करा दिए जाने के बाद कुल्लू या मनाली में कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय खोलने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

अजमेर में रेलवे की सम्पत्ति

*43. **श्री ओंकार सिंह लखावत**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अजमेर में रेलवे के पास कुल कितनी भूमि उपलब्ध है और कितने बंगले तथा क्वाटर्स (आवासीय) उपलब्ध हैं;

(ख) अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतू कितने आवासों की आवश्यकता है; और

(ग) क्या रेल कर्मचारियों के आवास हेतु रेल मंत्रालय द्वारा कोई राशि स्वीकृत की गई है; यदि हां, तो कितनी?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) अजमेर में रेलवे की कुल अपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल 440 हेक्टेयर है। बंगलों सहित कर्मचारी क्वार्टरों की कुल संख्या 2869 है। क्वार्टर के आबंटन के लिए 2007 कर्मचारी प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ग) जी हां। 49.61 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 36 कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है और वर्ष 1997-98 के दौरान 2 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

जंतर मंतर का संरक्षण

*44. **श्री ईश दत्त यादव**:
श्री राम गोपाल यादव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में कनाट प्लेस स्थित ऐतिपासिक स्मारक जंतर मंतर का आस्तित्व खतरे में है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त स्मारक के साथ-साथ मानव जीवन को भी खतरा है; और

(ग) यदि हां, तो मानव जीवन के साथ-साथ उक्त स्मारक के संरक्षण हेतु सरकार क्या और कब तक त्वरित कार्रवाई करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्पई): (क) से (ग) जंतर मंतर स्मारक परिसर को कोई खतरा नहीं है। स्मारक के पश्चिमी और दक्षिणी-पश्चिमी दिशा में लगी हुई भूमि नई दिल्ली नगर पालिका के नियंत्रण में है जिसे लगातार प्रदर्शनों, सार्वजनिक बैठकों इत्यादि के लिए प्रयोग किया जा रहा है। भूमि पर बड़ी संख्या में तम्बू गाड़े गए हैं और इनमें कुछ परिवार रह रहे हैं। चूंकि इससे स्मारक और संबंद्ध भूमि के दुरुपयोग की संभावना बनी हुई है, भारतीय पुरातत्व सवेंक्षण ने तम्बू वालों को हटाने और इस भूमि को भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण को स्थानान्तरित करने के लिए इस मामले को शहरी विकास मंत्रालय के साथ उठाया है।

MPs memorandum for rcvival of fertilizer units

*45. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether about 50 MPs had submitted a memorandum on 5th August, 1997 to his Ministry through the Prime Minister for revival of Durgapur, Barauni units of Hindustan Fertilizer Corporation

(HFC) and Ramagundam and Talcher units of Fertilizer Corporation of India (FCI) as per the Cabinet decision in principle in April, 1995;

(b) whether the above submission and the earlier Cabinet decision has been over-ruled;

(c) if so, the reasons for the same; and

(d) if not, how a decision has been

taken to suspend production/operations at Durgapur and Barauni?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The revival packages for Barauni, Durgapur and Namrups units of Hindustan Fertilizer Corporation Ltd. (HFC); and Sindri, Ramagundam and Talcher units of Fertilizer Corporation of India Ltd. (FCI) were approved by the Government in April 1995 with the stipulation that the fresh investment required be raised from healthy fertiliser cooperatives'financial institutions. These packages could not be implemented in the absence of tie up of funding arrangements. The revival packages were, thereafter, reformulated from the standpoint of funding by Financial Institutions in the light of the report of an expert Group led by Industrial Credit and Investment Corporation of India. Ltd. (ICICI). These packages envisaged a fresh investment of Rs. 3507 crore on the revamp of the Namrup, Durgapur and Barauni units of HFC; and Sindri, Ramagundam and Talcher units of FCI. Further reliefs and concessions, including write off of Government loans and accrued interest to the tune of Rs. 5006 crore were contemplated to make these pickages viable.

The revival pakage in respect of the Namrup units of HFC has been approved by the Government on 1.10.97. The eventual decision in respect of the remaining functional units of HFC & FCI, which will be subject to the approval of the Board for Industrial and Financial Reconstruction, would, *inter-alia,* take into account the considerations of unitwise viability and tie-up of the funding arrangements.

.(d) The production operations at Durgapur unit of HFC have temporarily been suspended by the Management of the company on account of frequent equipment problems, the resolution of which would necessitate a substantial capital investment. The tectmical constraints in the way of resumption of production in the Barauni unit are being addressed.

रेलवे स्टेशनों पर विक्रेताओं का चयन

*46. **श्री राम देव भंडारी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे स्टेशनों पर विक्रेताओं की नियुक्ति चयन संबंधी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या नियुक्ति के संबंध में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) वेंडरों के पदों के लिए सीधी नियुक्ति नहीं की जा रही है। केवल कमीशन के आधार पर पहले से कार्यरत बैरों/वेंडरों के संबंध में स्थायी आधार पर बैरों/वेंडरों के रुप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Dcalcrships/Distributorships for Women in Oil Products

*47. SHRI NAGENDRA NATH OJHA:
SHRI JALALUDIN ANSARI:

Will the MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to reserve 30 per cent of all dealerships and distributorships of oil products for. women;

(b) if so, the details in this regard;

(c) whether Government are aware that most of the dealerships and